देश-विदेश में गौरव बढ़ाने वाले प्रवासी राजस्थानी आज भी मिट्टी से जुड़े हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष फिर राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वैस्टमैंट समिट के आयोजन की घोषणा की

जयपुर, 10 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को जयपुर के जेईसीसी सभागार में प्रदेश के पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 के ऐतिहासिक समारोह का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सहित, कई नामी उद्योगपति तथा देश-विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वभर से आए प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले प्रवासी राजस्थानी आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और उन्होंने देश-दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा भी की। उन्होंने प्रवासी समुदाय से आग्रह किया कि वे राजस्थान आएं और खुशहाल एवं आधुनिक राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकार को संदेश के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों और राज्य के बीच भावनात्मक जुड़ाव तथा साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई। उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक, 'कमिटमेंट इन एक्शन' का भी विमोचन किया गया, जिसमें "राइजिंग राजस्थान" के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउण्ड ब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहले "प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025" समारोह का बुधवार को भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव सहित कई नामी उद्योगपति, देश-विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी उपस्थित थे।

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के लिए बधाई दी। उद्घाटन सत्र में "कमिटमैंट इन एक्शन" कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया।**

नौ विशिष्टजनों को "प्रवासी राजस्थानी सम्मान"

जयपुर, 10 दिसंबर। प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 कार्यक्रम में देश-विदेश में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों, अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनमचंद राठी, नरसी कुलरिया, सी.एम. मूंदड़ा और प्रदीप राठौड़ को "प्रवासी राजस्थानी सम्मान" से सम्मानित किया गया।

बैल्जियम से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घोटाले के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले, एंटीगा और बारबुडा भाग गया था। बाद में वह बेल्जियम में दिखाई दिया, जहां बताया जाता है कि वह इलाज के लिए गया था। भारत ने 27 अगस्त 2024 को बेल्जियम को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था, जो मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंटों पर आधारित था।

कोर्ट ऑफ कैसेशन के प्रवक्ता, अडवोका-जनरल हेनरी वैंडरलिंडन ने कहा, "कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील को खारिज कर दिया है। इसलिए, कोर्ट ऑफ अपील का फैसला बरकरार है।" एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही ठहराया था और इसे "लागू करने योग्य" कहा था।

एंटवर्प के कोर्ट ऑफ अपील के चार-सदस्यीय अभियोग कक्ष ने 29 नवंबर 2024 को जिला अदालत के प्री-ट्रायल चेंबर द्वारा जारी आदेशों में कोई कमी नहीं पाई। उन्होंने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने योग्य माना और चोकसी के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी।

'टैरिफ का कारण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया: "लेकिन अगर वे यह कहना चाहते हैं, तो उन्हें भारी शुल्क का भुगतान करते रहना होगा, और वे ऐसा नहीं करना चाहते।"

राजन की टिप्पणियों से ऑनलाइन बहस छिड़ गई, जिसमें कई मोदी समर्थकों ने यह तर्क किया कि भारत ने वैश्विक शक्तियों को संतुष्ट करने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य किया।

ये टिप्पणियाँ ट्रंप के उस दावे के संदर्भ में आईं, जिसमें वे लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्होंने अकेले भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष को रोका। पेनसिल्वेनिया के माउंट पोकोनो में एक रैली में समर्थकों को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कहा: "10 महीनों में, मैंने आठ युद्धों को खत्म किया, जिसमें कोसोवो (और) सर्बिया, पाकिस्तान और भारत, वे आपस में लड़ रहे थे, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया... आर्मेनिया और अजरबैजान।" उन्होंने मई के बाद से यह दावा लगभग 70 बार दोहराया है।

10 मई को एक युद्धविराम की घोषणा की गई, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद संबंधी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

भारत ने यह बताया है कि युद्धविराम की घोषणा पाकिस्तान के सैन्य संचालन निदेशक द्वारा उनके भारतीय समकक्ष से संपर्क करने के बाद हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी है। मोदी ने एक बार भी ट्रंप के दावे को खारिज नहीं किया है।

हालाँकि पाकिस्तान ने पहले इस दावे का विरोध किया था, बाद में उसने इसकी पुष्टि की और यहां तक कि ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया, और भारत पाक युद्ध में ट्रंप के नेतृत्व और कूटनीतिक हस्तक्षेप की सराहना की।

एनडीए गठबंधन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी सरकार की "पूर्व-नियोजित नीतियों" का परिणाम है। सांसद ने यह भी कहा कि युवा मंत्री पर हमला अनुचित था, क्योंकि उन्हें यह पद संभाले अभी कुछ ही महीने हुए हैं और वे पहले से चले आ रहे ढांचे की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, टीडीपी नेतृत्व को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गहरी चुप्पी से। टीडीपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय संकटों के समय पीएम मोदी पहले भी व्यक्तिगत तौर पर सामने आए हैं, चाहे वह बालासोर ट्रेन दुर्घटना रही हो, पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हमला रहा हो या लाल किले का विस्फोट मामला। "तो अब क्यों नहीं?" एक वरिष्ठ टीडीपी पदाधिकारी द्वारा पूछा गया यह प्रश्न दोनों दलों के बीच बढ़ती भावनात्मक दूरी का संकेत है।

टीडीपी इस चुप्पी को "गठबंधन धर्म" का उल्लंघन मान रही है। पार्टी को उम्मीद थी कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील समय में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उसके युवा मंत्री के समर्थन में आगे आएगा, खासकर इसलिये भी, कि एनडीए मौजूदा संसदीय स्थिति व्यवस्था में टीडीपी का समर्थन सरकार के लिये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से 72 घंटे से अधिक समय तक कोई भरोसा दिलाने वाला बयान न आने के बाद, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद आगे आए। उन्होंने न केवल राम मोहन नायडू को नैतिक समर्थन दिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा भी की कि उन्होंने "इस अभूतपूर्व संकट को परिपक्वता, पारदर्शिता और संतुलन के साथ संभाला।" हालाँकि दोनों दलों ने कहा है कि गठबंधन की मज़बूती यथावत बनी हुई है, लेकिन इस घटना ने एनडीए के भीतर मौजूद नाज़ुक तनावों को उजागर कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि गठबंधन राजनीति में राजनीतिक संवेदनशीलता और समय पर संवाद, दोनों ही ज़रूरी होते हैं, खासकर उस सरकार में, जहाँ संख्या बल मायने रखता हो और क्षेत्रीय सहयोगियों का वज़न का काफी हो।

राहुल ने गृह मंत्री शाह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु का जवाब देने में नाकाम रहे, जबकि उनसे उम्मीद थी कि सरकार इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देगी। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि चुनाव आयोग को पूरी छूट और पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई।

अमित शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने स्वयं को प्रतिरक्षा दी थी, जब अदालतों ने उनके चुनाव को अनुचित बताया था। अमित शाह ने कहा कि यही तो वोट चोरी है!! एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमित शाह इंदिरा गांधी की तुलना चुनाव आयोग से कर रहे हैं और क्या इंदिरा गांधी चुनाव हार नहीं गई थीं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो? राहुल गांधी ने कहा कि अपने पूरे जवाब के दौरान गृह मंत्री रक्षात्मक दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल आत्मविश्वासी नहीं थे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया कि विपक्ष को डिजिटल, मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य और पारदर्शी वोटर सूची क्यों नहीं दी जा रहीं, जबकि वे इसकी लगातार मांग कर रहे थे।

राहुल ने कहा, इस पर गृह मंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की संरचना पर पारदर्शी ऑडिट के मुद्दे पर भी वे पूरी तरह असहज दिखाई दिए। राहुल बोले, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया, इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल राज्यसभा में गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में कही गई कई बातों का जवाब देंगे और उनके द्वारा लोकसभा में बोले गए झूठ और आधे-अधूरे सच को मजबूती से चुनौती देंगे।

ट्रंप की प्रशासनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वह लिखते हैं, "वे अब बूढ़े दिखते हैं, जैसा कि उस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति दिखेगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि उनका संदेश बहुत बिखरा हुआ लगता है। पहले वह अधिक ध्यान केन्द्रित रख पाते थे।" उनकी इन टिप्पणियों ने राष्ट्रपति पद के भारी दबाव, बढ़ती उम्र का तनाव, और परिवार के सदस्यों द्वारा बताई गई बातों की विश्वसनीयता के बारे में चर्चाओं को फिर शुरु कर दिया है।

ट्रंप के हाल के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर राजनीतिक विश्लेषकों ने बारीकी से नज़र रखी हुई है। पिछले दिनों उनके कई भाषण बिना किसी खास कनैक्शन वाले विषयों पर भटकते रहे, जिस पर रिपब्लिकन दल के भीतर से भी आलोचना हुई कि वे महत्वपूर्ण समय पर मुख्य नीतिगत मुद्दों से भटक रहे हैं। कुछ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सामान्य रूप से, और बिना किसी विशेष व्यक्ति का मूल्यांकन किए, कहा है कि नेताओं के ऐसे पैटर्न अक्सर उनके निर्णय लेने की स्पष्टता पर सवाल उठाते हैं। जब ऐसे सवाल खुद नेता के परिवार की ओर से उठते हैं, तो वे और गंभीर माने जाते हैं।

सरकार के भीतर, ट्रंप का कैबिनेट किसी भी असाधारण संवैधानिक कदम पर विचार करता हुआ नहीं दिखता। 25वें संशोधन के तहत, कैबिनेट का बहुमत राष्ट्रपति को कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम घोषित कर सकता है और सत्ता उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। लेकिन इस संशोधन का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ट्रंप के मौजूदा सलाहकार, जो प्रशासन की नीतिगत दिशा तय करने में बड़ी भूमिका रखते हैं, ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार करेंगे, इसका कोई संकेत नहीं है। आलोचकों का कहना है कि स्टीफ़न मिलर, रसेल वॉट, जे.डी. वैंस और रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर जैसे प्रभावशाली लोग ट्रंप की अपने वफादारों के छोटे से समूह पर निर्भरता का लाभ उठाते हैं, इसलिए उन्हें चुनौती देने का कोई कारण नहीं देखते।

आख़िरकार, पूरी बहस शासन, पारदर्शिता और आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपति पद में अत्यधिक केन्द्रित सत्ता से जुड़ी व्यापक चिंताओं को दर्शाती है। ट्रंप तृतीय या राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कितना महत्व मिलता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में ट्रंप सार्वजनिक रूप से, और रोज़मर्रा के प्रशासनिक काम में, कैसा प्रदर्शन करते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908